No. UD-A(3)-3/2016.
Government of Himachal Pradesh
Department of Urban Development.

To

The Secretary.
H.P. Vidhan Sabha,
Shimla-171004.

Dated:Shimla-2, the 10-12- 2016.

Subject: Introduction of "Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2016.

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to introduce the "Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2016 in the current session of Himachal Pradesh Legislative Assembly. The aforesaid bill is to replace the "Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2016.

I, therefore, request you to obtain the permission from the Hon'ble Speaker to include the aforesaid Bill in the list of business for introduction, consideration and passing the same in the current session in relaxation of relevant rules.

Three authenticated copies of the above mentioned Bill are enclosed, herewith.

Yours faithfully,

[Sudhir Sharma]
U.D. Minister, H.P.

2016 का विधेयक संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 6 का संशोधन।

3. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2016 का विधेयक संख्यांक 21

.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह 04 अक्तूबर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 6 का संशोधन । 2 हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के परन्तुक में, "25" अंकों के स्थान पर "37" अंक रखे जाएंगे।

2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ। 3 (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश, के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6, नगर निगम में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों (सीटों) की अधिकतम संख्या सहित पार्षदों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए वार्डों के परिसीमन हेतु उपबन्ध करती है। अधिनियम में वर्तमान नगर निगम में अधिक से अधिक पच्चीस वार्डों के लिए ही उपबन्ध है और जिसके प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 3000 से कम न हो। अब ऐसा देखा गया है कि बहुत से वार्डों में जनसंख्या कई गुणा बढ़ गई है। इस कारण निर्वाचित पार्षदों को इतनी अधिक जनसंख्या वाले वार्डों के लोगों की मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए, समुचित नागरिक प्रसुविधाएं, संतुलित विकास और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के आशय से वार्डों की संख्या में बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित है। नगर निगम, शिमला का वर्तमान कार्यकाल मई, 2017 को पूरा होने जा रहा है और वार्डों का परिसीमन/पुर्नगठन करने के लिए उपायुक्त/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगभग आठ मास की अवधि अपेक्षित है, ताकि निर्वाचन पूर्व की समस्त औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) में तुरन्त संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4) 4 अक्तूबर, 2016 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 04 अक्तूबर 2016 को ही प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुधीर शर्मा)

प्रभारी मन्त्री।

धर्मशालाः

तारीखः 2016

वित्तीय ज्ञापन

.....शून्य.....

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

.....शून्य.....

————————

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुधीर शर्मा)

प्रभारी मंत्री

———————

(डॉ0 बलदेब सिंह)

प्रधान सचिव (विधि)

धर्मशालाः

तारीखः 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाली हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) के उपबन्धों के उद्धरण धाराएं :

6. वार्डों का परिसीमन.– पार्षदों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपायुक्त, ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए हों––

(क) नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में निम्नलिखित रीति के अनुसार विभक्त करेगा–

(i) प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित होगा; और

(ii) प्रत्येक वार्ड की, जहां तक संभव हो, जनसंख्या को समान रूप से बांटा जाएगाः

परन्तु प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या 3000 से कम नहीं होगी और सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 25 से अधिक नहीं होगी;

(ख) प्रत्येक वार्ड के क्षेत्र को अवधारित करेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन वार्ड या वार्डों का अवधारण करेगा जहां स्थान आरक्षित किए गए हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION

(SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

CLAUSES:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 6.
3. Repeal of H.P. Ordinance No.4 of 2016 and savings.

Bill No. 21 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1 (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of October, 2016.

Amendment of section 6.

2 In section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in the proviso, for the words “twenty five” the words “thirty seven” shall be substituted.

Repeal of H.P. Ordinance No. 4 of 2016 and savings

(1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2016 is here by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or any thing done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the Corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 6 of the HP Municipal Corporation Act,1994 provides for delimitation of wards for the purpose of election of Councillors in the Municipal Corporation including maximum number of seats to be filled by election. Presently, there is a provision to make a maximum of Twenty five wards in a Municipal Corporation and population in each ward shall not be less then 3000. Now it is seen that in many wards, the population has increased many folds. It is difficult for an elected councillor to cater to the demands and need of such high numbers, therefore, in order to ensure proper civic amenities, balanced growth and people's participation, the maximum number of wards are required to be increased. Present tenure of the Municipal Corporation Shimla is going to expire in the month of May, 2017 and a period of around eight months is required by the Deputy Commissioner/State Election Commission for delimitation/reorganization of wards so that all pre-election formalities are completed.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.13 of 1994) had to be amended urgently, therefore, the Governor Himachal Pradesh, in exercise, of the powers under clause(1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No.4 of 2016) on 4th day of October, 2016 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on the same day, Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

(SUDHIR SAHRMA)

Minister-in-charge.

DHARAMSHALA:

Dated …….. , 2016.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

Further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 13 of 1994)

(SUDHIR SHARMA)

Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)

Pr. Secretary (Law)

DHARAMSHALA:

The----------,2016

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT,1994 (ACT NO. 13 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section :

6. Delimitation of wards. - For the purposes of election of Councillors the Deputy Commissioner shall, in accordance with such rules as may be prescribed by the State Government,-

(a) divide the municipal area into wards in such a manner that,-

(i) one Councillor shall be elected from each ward ; and

(ii) as far as possible the population in each ward shall be equally distributed :

Provided that the population in each ward shall not be less than 3000 and the number of total seats to be filled by direct election shall not exceed twenty five;

(b) determine the territorial extent of each ward ; and

(c) determine the ward or wards in which seats are reserved under this Act.